(क) क्या गत छह महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की अत्यधिक कमी रही है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान राज्यों की मांग की तुलना में चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल की राज्य-वार कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन वस्तुओं के कोटे में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जनजातीय क्षेत्र में प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर वस्तु-वार कितनी राज-सहायता दी जाती है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं में भारी कमी के बारे में पिछले 6 माह के दौरान कोई सूचना केन्द्र सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल गेहूं, चीनी और मिट्टी के तेल की राज्यवार आवंटित मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध पर दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र सं० 24]**

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आवंटन में वृद्धि करने के अनुरोधों पर स्टाक की उपलब्धता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर मांग, मौसमजन्य कारकों, उठान के रुख, भूतकालिक कारणों आदि जैसे कारकों को मद्दे नजर रख कर विचार किया जाता है।

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर चावल और गेहूं दोनों उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान्य मूल्यों की तुलना में 50 रु० प्रति क्विंटल कम होते हैं।

Restructuring of Sick PSUs

808. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are considering to revamp and restructuring the Public Sector Units of sick nature as per the Common Minimum Programme; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Revamping and restructuring of loss making and sick Public Sector Undertakings is a continuous process. Revival and rehabilitation of industrial sick PSUs through the process of BIFR and non-industrial PSUs through administrative Ministries are a continuous process. The emphasis on this aspect in the Common Minimum Programme will further stimulate the endeavour.

Training and Self Development Projects for Women

809. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government has a proposal to launch projects for training and self development of women in middle level management of public sector undertakings;

(b) if so, the aims and objectives of the projects launched or proposed to be launched in that direction; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) Government of Inida, presently has no proposal to launch projects for training and self development of women in middle level management of PSUs. However, British Council Division, in association with the Deptt. of Economic Affairs and Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) has introduced "Springboard Women's Development Programme" as a special objective award for women in management training in public/private sector etc. The objective of this programme is to enhance women's access to decision making and leadership position at organisational level, as well as their optimal development and effectiveness in social and work roles to gain their full potential.